नवसर्जन संस्कृति

PRGI No. UPHIN/25/A1698

नवसर्जन संस्कृति

PUBLISHED HIINDI DAILY FROM LUCKNOW

वर्ष : 02
अंक : 028
दि. 28.05.2026,
गुरुवार
पाना : 04
किंमत : 00.50 पैसा

जेवर एयरपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए इलेक्ट्रिक बसें होंगी उपलब्ध - सीएम योगी

जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

(जीएनएस)।

लखनऊ, जेवर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के संचालन के साथ यात्रियों को आधुनिक सार्वजनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की तैयारी तेज हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक आवागमन के लिए प्राथमिक चरण में 110 इलेक्ट्रिक बसों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने बुधवार को स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन की चौथी बैठक की अध्यक्षता करते हुए नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यीडा क्षेत्र में 500 इलेक्ट्रिक बसों के संचालन की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि 15 जून से प्रस्तावित उड़ान संचालन से पहले सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ़ किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के तेजी से विस्तार पर भी जोर दिया।

अधिकारियों ने अवगत कराया कि प्रदेश में वर्तमान में लगभग 15.5 लाख इलेक्ट्रिक वाहन पंजीकृत हैं तथा वर्ष 2030 तक 10 हजार चार्जिंग स्टेशन विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अभी तक लगभग 2500 चार्जिंग स्टेशन संचालित हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने प्रस्तावित एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि बेहतर कनेक्टिविटी औद्योगिक विकास, निवेश और रोजगार सृजन को नई गति देगी। उन्होंने भूमि अधिग्रहण और विनिमय संबंधी कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि फरुर्खाबाद लिंक एक्सप्रेसवे के लिए लगभग 55 प्रतिशत भूमि प्राप्त की जा चुकी है।

सीएम योगी ने निर्देश दिए कि आगरा-लखनऊ-पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेसवे, जेवर लिंक एक्सप्रेसवे और झांसी लिंक एक्सप्रेसवे के लिए आवश्यक भूमि का अधिग्रहण जून माह के अंत तक पूरा कर लिया जाए। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि मेरठ-हरिद्वार एक्सप्रेसवे का एलाइनमेंट स्वीकृत हो चुका है तथा भूमि अधिग्रहण की कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

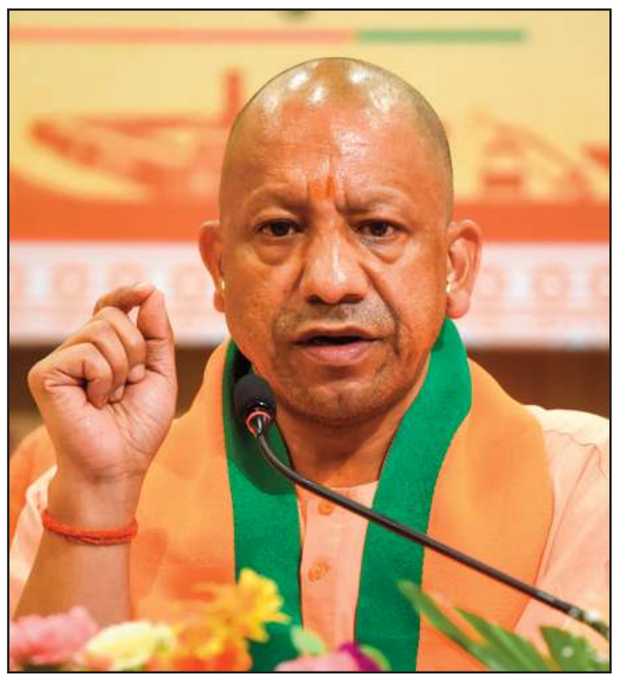

उन्होंने कहा कि निवेश संबंधी परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण और निवेशकों के साथ सतत संवाद बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में बताया गया कि मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के लिए 323 हेक्टेयर में से 301 हेक्टेयर भूमि पर कब्जा प्राप्त हो चुका है। डेवलपर चयन के लिए निविदा की अंतिम तिथि बढ़ाकर 6 जुलाई 2026 कर दी गई है। वहीं मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब के लिए 200 हेक्टेयर में से 144 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध हो चुकी है तथा शेष भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया जारी है।

मुख्यमंत्री ने औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिए मॉडल बिल्डिंग बायलॉज को निवेश अनुकूल व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बताते हुए कहा कि भवन स्वीकृति संबंधी प्रक्रियाओं को और अधिक सरल, पारदर्शी तथा समयबद्ध बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की समीक्षा करते हुए कहा कि ग्रामीण स्तर पर योजनाओं के प्रभावी संचालन के लिए पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराया जाए। बैठक में बताया गया कि राज्य स्तर पर 136 रिक्त पदों में से 40 पदों पर चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा शेष 96 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। जिला एवं विकासखंड स्तर पर 360 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित है।

उन्होंने लखनऊ में प्रस्तावित सीड पार्क और टेक्सटाइल पार्क परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि इन परियोजनाओं को प्रदेश के कृषि और औद्योगिक विकास से जोड़ते हुए तेजी से आगे बढ़ाया जाए। बैठक में बताया गया कि सीड पार्क परियोजना के संबंध में अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और प्रमुख बीज कंपनियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है तथा आगे की कार्यवाही पर सहमति बनी है। मुख्यमंत्री ने डिफेंस कॉरिडोर परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाने के लिए निवेशकों को आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराया जाए।

योगी आदित्यनाथ बोले—प्रदेश की विकास यात्रा बिना रुके आगे बढ़ रही है.

प्रयागराज सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का संगम बन चुका है. - मुख्यमंत्री योगी

(जीएनएस)।

नई दिल्लीः यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज नगर निगम के नवनिर्मित सदन हॉल और विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. उन्होंने कहा कि प्रदेश की विकास यात्रा बिना रुके आगे बढ़ रही है. यह यात्रा मां गंगा की धारा की तरह निरंतर है.

उन्होंने कहा कि प्रयागराज आज सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक विकास का संगम बन गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले शहर अव्यवस्था और गंदगी से जूझ रहा था. लेकिन 2019 के कुंभ ने इसे वैश्विक पहचान दिलाई. अब कुंभ और महाकुंभ की सुविधाएं स्थायी धरोहर बनेंगी. उन्होंने कहा कि शहर में 400 करोड़ रुपये की परियोजनाओं पर काम हो रहा है.

जोनल पार्क और शिवालिक पार्क जैसी परियोजनाएं वेस्ट टू वेल्थ का उदाहरण हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले धार्मिक स्थल उपेक्षित थे. अब अक्षय वट और सरस्वती कूप श्रद्धालुओं के लिए खुले हैं. महर्षि भारद्वाज आश्रम का भी पुनर्विकास किया गया है. उन्होंने कहा कि प्रयागराज स्मार्ट सिटी की दिशा में आगे बढ़ रहा है. गंगा एक्सप्रेसवे से दिल्ली की दूरी कम हुई है. शहर में पुल और सड़क परियोजनाएं तेजी से चल रही हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज अब माफिया मुक्त और सुरक्षित शहर है. उन्होंने विकास कार्यों को जनता के सहयोग से आगे बढ़ाने की बात कही. इस अवसर पर कई मंत्री और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे.

इबोला की वैक्सीन हो गई तैयार! किसने की इजाद और कैसे मिलेगी? कितनी असरदार?

जहां दुनिया एक तरफ इबोला वायरस के डर में जी रही है तो वहीं दूसरी तरफ अफ्रीकी देशों में इसे लेकर हाहाकार मचा हुआ है। अभी तक के डेटा के मुताबिक सेंट्रल एशिया में 241 लोग इससे जान गंवा चुके हैं जबकि इससे कितने प्रभावित हैं, कुछ पता नहीं। ये वायरस कोरोना जैसी तेजी से फैल रहा है लेकिन उससे बड़ा खतरा है इसका मृत्यु दर, जहां इसमें 50 प्रतिशत संभावना है कि इससे संक्रमित व्यक्ति की मौत हो सकती है, जो कोरोना में 2 प्रतिशत तक थी। इसी बीच एक राहत भरी खबर आ रही है।

'चुनाव में भाजपा को अच्छे से धो-पटककर सुखा देगी जनता'

अखिलेश ने सीएम योगी के बिजली के तार वाले बयान पर किया पलटवार

(जीएनएस)।

लखनऊ। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सपा सरकार में बिजली के तारों पर कपड़े सुखाने वाले बयान पर पलटवार किया है। सपा प्रमुख ने बुधवार को एक्स पर लिखा,'अगले चुनाव में जनता भाजपा को अच्छे से धो-पटककर हमेशा के लिए सुखा देगी। शुक्र है उप्र के असफल मुख्यमंत्री ने ये नहीं कहा कि इस महा विद्युत आपदा के पीछे दिल्लीवालों के भेजे हुए दूत की साजिश है।'

सपा प्रमुख ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए आगे लिखा, ये स्पष्ट किया जाए कि मुख्यमंत्री की समीक्षा बैठक में बिजली मंत्री आते नहीं हैं या बुलाए नहीं जाते हैं। अगर आते हैं तो माननीय से अनुरोध है कि उनके 'कंधे पर हाथ रखकर' एक तस्वीर आप पोस्ट कर दीजिए, जनता को आपकी 'आपसी गर्मी' से तो राहत मिल जाएगी, क्योंकि जनता ने आप दोनों को कभी एकांत में साथ देखा नहीं।

पीएम नरेंद्र मोदी से मिले सीएम थलापति विजय; हाथों में गुलदस्ता, चेहरे पर मुस्कान ...25 मिनट की मीटिंग से चढ़ेगा राजनीतिक पारा

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और टीवीके प्रमुख थलापति विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. मुख्यमंत्री बनने के बाद यह उनकी पहली आधिकारिक दिल्ली यात्रा थी. करीब 25 मिनट चली इस बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. विजय ने प्रधानमंत्री को लंबित परियोजनाओं, वित्तीय सहायता और मेकेदातु जल विवाद समेत विह्रि

(जीएनएस)।

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय उर्फ थलापति विजय ने बुधवार को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई. मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद राष्ट्रीय राजधानी की यह टीवीके प्रमुख विजय की पहली आधिकारिक यात्रा है.

दोनों नेताओं की इस मुलाकात की सामने आई तस्वीर को लेकर चचाओं का बाजार गरम है. थलापति विजय सिंपल ब्लैक ब्लेजर, व्हाइट शर्ट और ब्लैक पैंट में पीएम से मिलने पहुंचे. वह पीएम के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर पहुंचे. पीएम मोदी भी हमेशा की तरह मुस्कुारते हुए विजय का स्वागत किया. सामने आई तस्वीरें देखकर साफ पता चल रहा है कि दोनों नेताओं की गर्मजोशी के साथ मुलाकात हुई है.

सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि साल 2014 में भी विजय और पीएम मोदी की मुलाकात हुई थी.

सूत्र बता रहे हैं कि करीब दो साल बाद पीएम मोदी और थलापति विजय की मुलाकात हुई है. दोनों नेताओं के बीच करीब 25 मिनट मीटिंग होने की बात कही जा रही है. इस मुलाकात को लेकर इसलिए बातें हो रही हैं क्योंकि इस वक्त थलापति विजय कांग्रेस का समर्थन लेकर सरकार चला रहे हैं. दूसरी तरफ तमिलनाडु में बीजेपी की सहयोगी अक्ज्टड के विधायकों के टूटकर टीवीके में आने की भी चर्चा है.

सीएम विजय ने पीएम मोदी के सामने इन मुद्दों पर की बात-मुख्यमंत्री विजय ने नीदरलैंड से अनाइमंगलम कॉपर प्लेट्स वापस लाने में मदद के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया. तमिलनाडु सरकार के सभी कार्यक्रमों की शुरूआत में तमिल थाई वज्थू जारी रखने को लेकर गृह मंत्रालय से स्पष्टता मांगी.

विजय ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु में DRDO का सेंटर फॉर एयरबोर्न सिस्टम्स (CABS) स्थापित करने की अपील की. डिफेंस और एयरोस्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए राज्य में निवेश बढ़ाने की मांग रखी. कर्नाटक के प्रस्तावित मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट पर चिंता जताई और इसे कावेरी ट्रिब्यूनल व सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के खिलाफ बताया.

काकोली घोष दस्तीदार कौन हैं? TMC सांसद ने सभी पदों से इस्तीफा देकर ममता दीदी को दिया तगड़ा झटका

तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की लोकसभा सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सभी पदों से अचानक इस्तीफा दे दिया है। घोष दस्तीदार का इस्तीफा टीएमसी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, जब पार्टी पहले से ही नेताओं के दूसरे दलों में जाने की चुनौती का सामना कर रही है।

बारासात से प्रतिनिधित्व करने वाली दस्तीदार ने इस फैसले के पीछे "व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं" का तर्क दिया है लेकिन , राजनीतिक गलियारों में यह इस्तीफा भाजपा नेता और पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी से उनकी हालिया मुलाकात से जोड़ा जा रहा है, जिसने बंगाल की सियासत में हलचल मचा दी है। सूत्रों के अनुसार, काकोली घोष दस्तीदार लंबे समय से पार्टी नेतृत्व के कुछ फैसलों से नाराज चल रही थीं। खासतौर पर उन्हें लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक पद से हटाने को जिम्मेदारी दिए जाने के बाद से उनकी नाराजगी खुलकर सामने आने लगी थी।

केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के ठिकानों पर ईडी के ताबड़तोड़ छापे से नाराज हुए अरविंद केजरीवाल, लगाए आरोप

(जीएनएस)।

27 मई (बुधवार) सुबह प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर राज्य में सियासी भूचाल ला दिया। तिरुवनंतपुरम से कन्नूर तक हुई इस अचानक कार्रवाई ने पूरे राज्य में हड़कंप मचा दिया, जिसके केंद्र में विजयन की बेटी टी. वीणा और उनकी पूर्व आईटी कंपनी एक्सालॉजिक है।

विपक्षी दलों ने इस कार्रवाई को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उन्होंने इसे भाजपा द्वारा केंद्रीय एजेंसियों का "खुला दुरुपयोग" कहा, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पार्टियों को निशाना बनाना है। वहीं अब विजयन के खिलाफ ईडी की इस छापेमारी पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने जमकर हमला बोलते हुए नाराजगी जताई। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया।

केजरीवाल ने एक्स पर लिखा, "केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी की रेड, भाजपा द्वारा सेंट्रल एजेंसियों का एक और खुला गलत इस्तेमाल है, ताकि वे क्षेत्रीय विपक्षी पार्टियों को टारगेट कर सकें और डेमोक्रेसी को कमजोर कर सकें।"

केजरीवाल ने अपने पोस्ट में भाजपा-कांग्रेस के गठजोड़ पर भी सवाल उठाए। "कांग्रेस के 'निष्क्रियता' की शिकायत के तुरंत बाद ईडी की रेड, भाजपा-कांग्रेस के रिश्ते पर सवाल उठाती है," उन्होंने कहा। यह छापेमारी अब एक बड़े राजनीतिक विवाद का रूप ले चुकी है।

क्या है पूरा मामला, क्यों विजयन के घर में पड़ा ईडी का छापा

यह विवाद टी. वीणा की कंपनी एक्सालॉजिक और निजी खनन फर्म कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (CMRL) से जुड़ा है। आरोप है कि 2017 से 2021 के बीच एक्सालॉजिक को CMRL से बिना किसी वास्तविक आईटी सेवा के हर महीने भारी "रिटेनर फीस" दी गई।

दिल्ली एसआईआर 20 जून से शुरू होगा वोटर लिस्ट सुधार का महा-अभियान

दिल्ली में मतदाता सूची को पूरी तरह अपडेट करने के लिए चुनाव आयोग अब बड़ा अभियान शुरू करने जा रहा है। राजधानी में तेजी से बढ़ती आबादी, लगातार हो रहे पलायन और हर साल बड़ी संख्या में नए वोटर्स के

जुड़ने की वजह से चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया लागू करने का फैसला लिया है। इस अभियान के तहत चुनाव अधिकारी घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे और यह जांच करेंगे कि कौन लोग अभी भी दिल्ली में रह रहे हैं, किन लोगों का नाम नए सिरे से जोड़ा जाना चाहिए और किन लोगों के नाम हटाने की जरूरत है।

'महंगाई की आग से...', पीएम मोदी ने गर्मी को लेकर शेयर की पोस्ट तो खरगे ने कसा तंज, कहा- लूट पर बोलिए

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरने ने पीएम मोदी की एक पोस्ट को लेकर रिएक्शन दिया है. उन्होंने केंद्र पर महंगाई को लेकर तंज कसा.

(जीएनएस)।

उत्तर भारत के कई राज्य भीषण गर्मी की चपेट में हैं. तापमान बढ़ने की वजह से लोगों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है. इस मसले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार (27 मई) को एक पोस्ट शेयर की, जिसमें लोगों को गर्मी से बचने के लिए किया. प्रधानमंत्री मोदी की इस पोस्ट को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने तंज कस दिया. उन्होंने कहा कि लोग गर्मी से तो बच लेंगे, लेकिन महंगाई की आग से कैसे बचेंगे.

खरगे ने एक्स पर पोस्ट शेयर की. उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए लिखा, 'गर्मी तो झेल लेंगे, पर भाजपा प्रायोजित महंगाई की आग से आम जनता के पसीने छूट रहे हैं. अपनी सरकार की लूट पर भी कभी कुछ बोलिए, मोदी जी?' खरगे ने मंगलवार को भी एक पोस्ट शेयर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था, 'मैंने कल ही कहा था कि ये मोदी जी की रणनीति है. ये एक तरह से स्लो पॉइजनिंग है, जो गरीबों को तबाह कर रही है. मोदी सरकार हर दिन थोड़ी-थोड़ी कीमतें बढ़ा रही है.'

लखनऊ की श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत में पुलिस का एक्शन, पति भूपेंद्र और ससुर कौशलेंद्र प्रताप सिंह को किया गिरफ्तार

(जीएनएस)।

लखनऊ। भोपाल की ट्विशा शर्मा जैसा मामला लखनऊ में भी सुर्खियों में हैं। यहां के ठाकुरगंज में 29 वर्ष की बैंकर श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के प्रकरण में श्वेता सिंह के पति भूपेंद्र और ससुर कौशलेंद्र प्रताप सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

श्वेता के पिता ¨ उमेश सिंह ने उसके पति के साथ ही सास-ससुर और देवर के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। श्वेता का विवाह महज छह महीने पहले हुआ था। उसके परिवार के लोगों को का आरोप है कि श्वेता को दस लाख रुपये और स्कॉर्पियो गाड़ी के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था।

हरदोई रोड के विश्वास नगर निवासी उमेश कुमार सिंह ने बताया कि बीते वर्ष नवंबर में 26 वर्षीय बेटी श्वेता सिंह का विवाह काशी विहार निवासी कौशलेंद्र प्रताप सिंह से किया था। वह लालकुआं पर पैथालाजी चलाते हैं। पिता ने बताया कि रविवार रात श्वेता ने अपनी बड़ी बहन से फोन पर बात की थी तो उसका स्वास्थ्य एकदम ठीक था। कुछ ही देर बाद कौशलेंद्र ने फोन कर बताया कि श्वेता ने फंदे से लटककर जान दे दी है।

पिता का आरोप है कि ससुरालीजन शादी के बाद से ही कार की मांग कर उसे प्रताड़ित करते थे। घटना के बाद खुद ही उसे लेकर अस्पताल भी पहुंच गए थे, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। श्वेता की मां का हाल ही में आपरेशन हुआ है और वह प्रयागराज के निजी अस्पताल में भर्ती हैं। पिता ने कार्रवाई की मांग की है। इंस्पेक्टर ओमवीर सिंह ने बताया कि मुकदमा दर्ज किया गया है।

श्वेता के ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप

श्वेता सिंह की संदिग्ध मौत के उसकी बहन कोमल और ज्योति ने पति भूपेंद्र और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वे लोग श्वेता से कहते थे कि तुम मेरे बेटे के पैर की धूल भी नहीं हो', वे श्वेता को परिवार से दूर करना चाहते थे। श्वेता की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उसकी मौत की वजह हैगिंग बताई गई है। कोमल ने कहा कि भूपेंद्र तो श्वेता की 24 घंटे निगरानी करता था। मायके नहीं आने देता था, वह चाहता था कि श्वेता अपने परिवार से पूरी तरह कट जाए। वे लोग उससे कहते थे कि तुम मेरे बेटे के पैर की धूल भी नहीं हो।

जॉब छुड़ाकर बनाया हाउसवाइफ

श्वेता के परिवार के लोगों ने बताया कि वो एचडीएफसी बैंक के डेबिट कार्ड डिपार्टमेंट में काम करती थी। शादी तय होते ही भूपेंद्र और ससुराल वालों ने उसकी नौकरी छुड़वा दी। उन्होंने झूठा आश्वासन देकर कहा कि शादी के कुछ महीनों बाद फिर से कर लेना। श्वेता को पता ही नहीं था कि उसके ससुराल वाले उसे फुल टाइम हाउसवाइफ बनाकर रखना चाहते हैं।

पैर पकड़ गिड़गिड़ाए थे पिता, वो खींच कर ले गया

श्वेता की दोनों बहनों ने बताया कि विदाई वाले दिन ही ससुराल वालों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। भूपेंद्र और पिता ने दस लाख रुपये और स्कॉर्पियो गांड़ी की मांग कर दी, कहने लगे हमें तुरंत चाहिए। हमने तो औकात से बढ़कर शादी की है और अब हमारे पास देने को कुछ और नहीं बचा है। यह बात कहते हुए पिता उनके सामने गिड़गिड़ाए। भूपेंद्र के पैर पकड़े और हाथ जोड़े, लेकिन उसने उफ तक नहीं की। विदाई के समय उसने श्वेता को खींचते हुए कार में बैठाया और चला गया, हम लोगों को उससे मिलने तक नहीं दिया था।

सीएम योगी 29 मई को मऊ दौरे पर, विकास परियोजनाओं की देंगे सौगात, मधुबन से सदर तक हाई अलर्ट

(जीएनएस)।

मऊः मऊ में 29 मई को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित दौरा प्रशासन और पुलिस विभाग के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। मुख्यमंत्री जिले के मधुबन और सदर विधानसभा क्षेत्रों में आयोजित कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। हालांकि अभी तक विस्तृत प्रोटोकॉल प्रशासन को नहीं मिला है, लेकिन तैयारियां युद्धस्तर पर जारी हैं। पिछले दो दिनों से अधिकारी लगातार कार्यक्रम स्थलों का निरीक्षण कर रहे हैं।

जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री सुबह करीब 10 बजे मधुबन विधानसभा क्षेत्र के पांति गांव पहुंचेंगे, जहां विभिन्न विकास परियोजनाओं और सरकारी योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद मधुबन के गांधी मैदान में आयोजित विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान कई सरकारी भवनों का उद्घाटन

भी किया जाएगा और लाभार्थियों को प्रशस्ति पत्र व चेक वितरित किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

सुरक्षा व्यवस्था कड़ी

मुख्यमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था बेहद कड़ी कर दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर हेलीपैड का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी लगातार व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बुधवार को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने मधुबन पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। बाहर से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी बुलाई गई है और सुरक्षा में वरिष्ठ अधिकारियों की तैनाती की गई है।

क्या बोले जिम्मेदार?

मधुबन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री सदर विधानसभा क्षेत्र पहुंचेंगे, जहां एक निजी अस्पताल के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे और सभा को संबोधित करेंगे। पुलिस अधीक्षक कमलेश बहादुर ने बताया कि सुरक्षा के लिए चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं और अधिकारियों के साथ लगातार ब्रीफिंग चल रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर पूरे जिले में प्रशासनिक गतिविधियां तेज हो गई हैं।

1180 करोड़ की कोकीन जब्त, ब्राजील से पहुंचा था गुजरात, 3 विदेशी गिरफ्तार

(जीएनएस)।

गुजरात के कच्छ तट पर एक बड़े अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा हुआ है। Gujarat Anti-Terrorism Squad और Indian Coast Guard के संयुक्त ऑपरेशन में करीब 1180 करोड़ रुपए कीमत की 118 किलो कोकीन जब्त की गई।

यह खेप ब्राजील से कई देशों और कराची होते हुए गुजरात पहुंची थी। मामले में अब तक तीन विदेशी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया। जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि भारत में यह ड्रग्स किस नेटवर्क तक पहुंचाई जानी थी।

मुंद्रा तट पर ऐसे पकड़ा गया जहाज

यह कार्रवाई गुजरात के मुंद्रा तट के पास की गई। अधिकारियों को पहले से सूचना मिली थी कि समुद्री रास्ते से बड़ी मात्रा में ड्रग्स लाई जा रही है। इसके बाद कोस्टगार्ड और अळर ने संयुक्त निगरानी शुरू की। संदिग्ध कंटेनर जहाज को समुद्री सीमा के भीतर ट्रैक किया गया। जहाज करीब 5 नॉटिकल मील दूर लंगर डाले खड़ा था। कई घंटों तक नजर रखने के बाद अधिकारियों ने

देखा कि जहाज से कुछ बैग समुद्र में फेंके जा रहे हैं, जिसके बाद तुरंत ऑपरेशन शुरू किया गया।

तीन विदेशी आरोपी गिरफ्तार

छापेमारी के दौरान जहाज पर मौजूद लोगों को पकड़ने की कोशिश की गई। इस दौरान एक आरोपी समुद्र में कूदकर फरार हो गया, जिसकी तलाश अभी जारी है। वहीं तीन विदेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। इनमें क्लैविन चुकवुमा, ब्यारुहांगा जेम्स और जुम्मा नासिर उमर शामिल हैं। शुरूआती जांच में सामने आया है कि ड्रग्स की यह खेप दिल्ली के द्वारका इलाके तक पहुंचाई जानी थी। एजेंसियां अब पूरे नेटवर्क और भारत में मौजूद संपर्कों की जांच कर रही हैं।

ब्राजील से कराची होकर पहुंची खेप

जांच में पता चला है कि जहाज ब्राजील से निकला था और कई लैटिन अमेरिकी देशों, मेक्सिको, अमेरिका और कराची होते हुए गुजरात पहुंचा। इससे साफ है कि यह एक बड़ा अंतरराष्ट्रीय ड्रग्स रैकेट हो सकता है। सुरक्षा एजेंसियां यह भी जांच कर रही हैं कि पाकिस्तान के रास्ते इस नेटवर्क को कौन चला रहा था। अधिकारियों का मानना है कि समुद्री रास्ते का इस्तेमाल कर भारत में ड्रग्स पहुंचाने की कोशिश लगातार बढ़ रही है, इसलिए तटीय सुरक्षा और निगरानी को और मजबूत किया जा रहा है।

पहले भी पकड़ी जा चुकी है बड़ी खेप

गुजरात के समुद्री इलाके में इससे पहले भी कई बड़े ड्रग्स ऑपरेशन हो चुके हैं। अप्रैल 2025 में पोरबंदर के पास करीब 1800 करोड़ रुपए की 300 किलो ड्रग्स पकड़ी गई थी। उस समय भी तस्करों ने समुद्र में पैकेट फेंककर भागने की कोशिश की थी। लगातार सामने आ रहे मामलों से साफ है कि गुजरात का समुद्री इलाका अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करों के निशाने पर है। एजेंसियों का कहना है कि आने वाले समय में समुद्री निगरानी और ऑपरेशन और तेज किए जाएंगे।

शारीरिक संबंध बनाओ या ढाई लाख दो, नहीं तो वीडियो होगा वायरल

(जीएनएस)।

मछलीशहर। क्षेत्र के एक ग्रामीण बाजार की युवती से उसके इंस्टाग्राम दोस्त ने फोन कर कहा कि शारीरिक संबंध बनाओ या ढाई लाख रुपये दो, नहीं तो तुम्हारा वीडियो वायरल कर दूंगा। बार-बार दबाव बनाने और बदनामी से डरी युवती ने दोस्त पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। युवती की प्रयागराज कमिश्नरेट के थाना बारा अंतर्गत कौझियारा कुबुद्दी गांव निवासी संदीप कुमार से इंस्टाग्राम पर दोस्ती हुई थी। युवती के अनुसार लगभग छह महीने पूर्व से युवक से इंस्टाग्राम पर चैटिंग होती थी। चैटिंग और वीडियो कॉलिंग का फायदा उठाकर युवक ने गलत तरीके से गंदा वीडियो बना लिया। उसके बाद युवक संदीप युवती से शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाने लगा। युवती के मना करने पर ढ़ाई लाख रुपये की मांग की। युवती का आरोप है कि न देने पर वीडियो परिजनों और सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दे रहा है। घटना से परेशान युवती ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। मछलीशहर कोतवाली प्रभारी विनीत राय ने कहा कि युवती की तहरीर पर आरोपी युवक पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई है। जल्द ही आरोपी की गिरफ्तारी की जाएगी।

भारत ने क्वाड से पिंड छुड़ाया, मतलबी दोस्तों के मतलब के लिए क्यों खुद को घसीटते रहें

(जीएनएस)।

भारत ने कूटनीतिक चालाकी दिखाते हुए क्वाड की कमान ऑस्ट्रेलिया को सौंपकर इस समूह से धीरे-धीरे अपना पिंड छुड़ा लिया है. बीते वर्षों में जिस तरह दुनिया के हालात बदले हैं, जिस तरह अमेरि का मतलबी हुआ है, उससे क्वाड अपनी प्रासंगिकता खो चुका है. 'नेशन फर्स्ट' की नीति पर चलते हुए भारत अब पश्चिमी देशों के स्वार्थ के लिए खुद को घसीटने और उधार की दुश्मनी मोल लेने के मूड में बिल्कुल नहीं है.

आज यानी 26 मई, 2026 को क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक दिल्ली में पूरी हो गई. चार्टर और कागजों पर तो कूटनीति पूरी हो गई, लेकिन सच ये है कि भारत ने क्वाड से पिंड छुड़ा लिया है. चार दस्तावेज जारी किए. क्रिटिकल मिनरल, एनर्जी, इंडो पैसिफिक में निगरानी पर सहमति बनी. पश्चिमी एशिया का जिक्र भी आया. स्ट्रेट ऑफ हॉरमुज से बिना टोल दिए आवाजाही पर बल दिया गया. लेकिन खबर ये नहीं है. खबर ये है कि भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने जिस मकसद से क्वाड का गठन किया, वो मकसद ही खत्म होता दिख रहा है. क्वाड के खात्मे की पटकथा लिख दी गई है. भारत ने ऑस्ट्रेलिया को क्वाड का बैटन पकड़ा दिया है. दिल्ली में इस साल होने वाली क्वाड नेताओं की शीर्ष बैठक शायद अब कभी न हो. इस लिहाज से हमने चालाकी से ऑस्ट्रेलिया को बागडोर थमाकर कूटनीति का शानदार नमूना

पेश किया है.

2017 में क्वाड बना क्यों था? ये चीन की गुस्ताखी का जवाब देने के लिए बना था. चार्टर में साफ था कि ये मिलिट्री अलायंस नहीं है लेकिन चीन को मैसेज देना था. इसकी जरूरत अमेरिका को थी. प्रशांत महासागर और एटालांटिक महासागर पार कर चीन तक पहुंचना उसके बूते की बात नहीं थी . अमेरिका को बैसाखी चाहिए था. ये बैसाखी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान से बेहतर कौन दे सकता था. चीन से दो जंग लड़ चुके जापान में अमेरिकी बेस है. ऑस्ट्रेलिया का भूगोल साउथ चाइना सी के पास है. भारत तो चीन का भुक्तभोगी रहा है.

लेकिन पिछले 9 साल में दुनिया 360 डिग्री घूम चुकी है. हमारी चीन से लद्दाख और अरुणाचल में झड़प हो चुकी. उसके बाद रिश्ते वापस बेहतर हो रहे. ब्रिक्स समिट कजान में मोदी-जिनपिंग ने इसकी शुरूआत की. फिर 31 अगस्त, 2025 को चीन के तियानजिन में मोदी झ पुतिन और जिनपिंग की इस तस्वीर ने वॉशिंगटन तक कोहराम मचा दिया. दोनों देशों के बीच फ्लाइट शुरू हो चुकी है. एफडीआई में छूट देने की बात हो रही है. ये रिपोर्ट भी आ चुकी कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ इस्तेमाल के लिए एक्स्ट्रा परमाणु पनडुब्बी मांगी जिसे देने से चीन ने मना कर दिया.

उधर ट्रंप ने क्या किया? पहले टैरिफ की लड़ाई लड़ी. 100 परसेंट से ज्यादा टैक्स लगा दिए। फिर खुद की हालत खराब हुई तो लाइन पर आ गए. आज बेसलाइन टैरिफ 25 परसेंट है. यूक्रेन वॉर में यूरोप से रिश्ते बिगाड़ लिए. धमकी देने लगे कि जी-2 बनेगा तो क्या होगा. ये दरअसल जी-7 और जी-20 के ठेंगा दिखाना था. मतलब था कि अगर चीन और अमेरिका एक हो जाएं तो..फिर अमेरिका ने ताइवान को डिफेंस एक्सपोर्ट रोक दिया. खुद बीजिंग पहुंच गए और सुनते रहे जब जिनपिंग ने अमेरिका को एक गिरता हुआ देश कह दिया. ट्रंप को महसूस हो गया कि चीन से बिगाड़ कर कुछ नहीं हो सकता. इसलिए ताइवान को भी त्याग दिया.

फिर ईस्ट चाइना सी या साउथ चाइना सी में चीन की दादागीरी हो या न हो, इससे अमेरिका को मतलब ही क्या रह गया? जब तुम्हें मतलब नहीं तो हमें उधार की दुश्मनी लेने की जरूरत क्यों है?

अमेरिका की उदासीनता पिछले दो साल में और ज्यादा बढ़ गई जब क्वाड की अध्यक्षता हमारे पास आई यानी भारत के पास आई. हम चारों सदस्य देशों के राष्ट्राध्यक्षों का इंतजार करते रहे लेकिन किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया. 2024 में बैठक होनी थी तो जो बाइडन ने तबीयत का बहाना बना दिया. बैठक विलमिंगटन में अपने होम टाउन में रखी. उसके बाद ट्रंप को टाइम नहीं है. उधर अपने को महाजन समझने वाला अमेरिका ब्रिक्स पर अटैक करता रहा जिसमें भारत, ब्राजील, रूस, चीन और साउथ अफ्रीका शामिल है. बाद में इसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया भी शामिल हो गए. ट्रंप बार-बार आरोप लगाते हैं ब्रिक्स अपनी करेंसी लाएगा और डॉलर को रिप्लेस करने की साजिश रच रहा है. अरे भाई रूस हमारा टाइम टेस्टेड मित्र है. ईरान से पुराने रिश्ते रहे हैं. हम ग्लोबल साउथ के लीडर के नाते इस ग्रुपिंग को देखते हैं. इस पर रूस और चीन हमारे साथ है. तुम जब मर्जी ईरान से जंग शुरू कर दो, जब मर्जी वेनेजुएला पर अटैक कर दो, रूस पर बैन लगा दो और हम तुम्हारे डॉलर के भरोसे बैठे रहें. ये नहीं हो सकता.

ये भी एक बड़ा कारण है कि क्वाड को स्वाहा कर दिया जाए. ऐसा पहली बार नहीं होगा जब कोई बहुराष्ट्रीय व्यवस्था गर्त में मिल जाएगी. इससे पहले भी लीग ऑफ नेशंस, सेंट्रल ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन, साउथ ईस्ट एशिया ट्रिटी ऑर्गेनाइजेशन (सीटो) काल के गाल में समा चुके हैं. सबके पीछे एक कारण. प्रासंगिकता खत्म हो जाना. तो क्वाड की आयु दस साल की ही थी. अब हमारे लिए तो इसका मतलब खत्म है. और हम राष्ट्र प्रथम की राह पर हैं. मतलबी दोस्तों के मतलब के लिए कितना खुद को घसीटते रहें.

लखनऊ में चोरी की बिजली से होटल में चल रहे थे 13 एसी

10 लाख का भरना होगा जुमार्ना

(जीएनएस)।

लखनऊ। राजधानी में बिजली संकट के पीछे बिजली चोरी भी बड़ा कारण है। अमौसी जोन में बिजली संकट कम होते ही अभियंताओं की टीम घर घर चेकिंग करने में लग गई है। ऐसे ही उपभोक्ताओं को चिन्हित करने का काम अमौसी जोन के निलमथा में अधिशासी अभियंता एके शुक्ला ने किया। शुक्ला ने टीम के साथ एक निजी होटल में जांच की तो यहां बड़े पैमाने पर हो रही बिजली चोरी देखकर भौचक्के रह गए।

परिसर में तेरह एसी मिले और एक दर्जन पंखे व अन्य उपकरण चलते हुए पाए गए। टीम ने मौके पर ही 2.80 लाख का शमन शुल्क और दस लाख रुपये से अधिक का जुमार्ना

वसूलने की तैयारी कर ली है। वहीं बिजली चोर पर चोरी की धाराओं में मामला भी दर्ज करते हुए कनेक्शन काट दिया गया है। उधर अधिकारियों और कर्मचारियों की संभावित मिलीभगत की भी जांच शुरू कर दी गई है।

टीम ने छापा का समय मंगलवार रात का चुना। टीम यहां 10.20 बजे पहुंची। जांच के दौरान 28 किलोवाट लोड पर बिजली चोरी पाई गई। अमौसी जोन के मुख्य अभियंता राम कुमार ने बताया कि नीलमथा के डिप्टीगंज हरिहरपुर आदर्शनगर स्थित होटल मिराकी इन में छापा मारा। प्रकाशनी शेखर के इस होटल में घरेलू बिजली से होटल चलता पाया गया, जिसमें नौ किलोवाट का कनेक्शन था।

होटल संचालक श्री फेज केबल को छज्जे के अंदर काट करके उसमें दूसरी केबल को जोड़कर बिजली चोरी करते पकड़ा गया। जांच में दो मंजिल के होटल में 12 पंखे और 13 एसी चोरी वाली बिजली से जुड़े पाए गए। जांच दल में एसडीओ आशुतोष वर्मा, जेई राजेश कुमार, इंसपेक्टर वीरेंद्र सिंह आदि शामिल थे।

बिजली कटौती बर्दाश्त नहीं! सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री की सख्ती का दिखा असर, गस्त करते नजर आए अधिकारी

सीएम योगी और ऊर्जा मंत्री ने बिजली कटौती को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया है। इसके बाद मऊ में बिजली विभाग के अधिकारी ग्रामीण अंचलों में गश्त करते नजर आए।

(जीएनएस)।

मऊः भीषण गर्मी में बिजली कटौती के खिलाफ हर तरफ आवाजें उठ रही हैं। इसको लेकर कभी सत्ता पक्ष तो कभी विपक्ष बिजली विभाग को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इस बीच भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को निर्बाध बिजली आपूर्ति के लिए मंगलवार को सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने एक बैठक के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों को सख्त लहजे में कहा कि किसी भी कीमत पर बिजली की कटौती को बर्दश्त नहीं किया जाएगा।

गश्त करते नजर आए बिजली विभाग के अधिकारी

सीएम योगी ने कहा कि उपभोक्ता हितों में निर्बाध बिजली आपूर्ति विभागीय अधिकारी सुनिश्चित करें। इसको लेकर अब बिजली विभाग के अधिकारियों ने भी अब पूरी तरह से अपनी कमर कस ली है। इसके नतीजन देर रात लगभग ग्यारह बजे जनपद मऊ के विद्युत वितरण खंड द्वितीय के अधिशासी अभियंता महेश विश्वकर्मा बिजली विभाग की टीम के साथ ग्रामीण अंचलों में गश्त करते नजर आए।

'निर्बाध बिजली आपूर्ति के प्रतिबद्ध है ऊर्जा विभाग'

रात्रि गश्त के दौरान विद्युत ट्रांसफॉमेर्रों और बिजली आपूर्ति का जायजा लेने पहुंचे अधिशासी अभियंता महेश विश्वकर्मा ने नवभारत टाइम्स से विशेष बातचीत में कहा कि उपभोक्ता बंधुओं के हित में निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित कराने के लिए हमारे बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी 24 घंटे लोगों के बीच में लगे हुए हैं। जिससे किसी भी प्रकार से विद्युत आपूर्ति बाधित ना हो। हम लोग निरंतर विद्युत ट्रांसफॉमेरी की स्थिति का जायजा भी ले रहे रहे हैं। इसके साथ ही उपभोक्ताओं और विद्युत कर्मियों से बातचीत करके हम ट्रिपिंग के कारणों को भी जानने का प्रयास कर रहे है,जिससे उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो।

'प्रदेश में बिजली का कोई संकट नहीं'

बातचीत के दौरान महेश विश्वकर्मा ने कहा कि प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई बिजली संकट नहीं है। ट्रासफार्मरों में ओवर हीटिंग के कारण समस्याएं ना आयें इसके लिए रोस्टर प्लान के हिसाब से उपभोक्ता बंधुओं को बिजली आपूर्ति की जा रही है। जिससे उन्हें निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति मिलती रहे।

आवश्यकता अनुसार ही बिजली का करें इस्तेमाल

नवभारत टाइम्स से विशेष बातचीत में महेश विश्वकर्मा ने ट्रिपिंग के कारणों पर भी विशेष चर्चा की। उन्होंने बताया कि शाम के समय लगभग दस बजे तक उपभोक्ताओं के द्वारा बिजली की पीक डिमांड होती है। जिसके कारण इस समय ट्रिपिंग की समस्या विशेष तौर से देखने को मिलती है।

'एक साथ सारे उपकरणों का प्रयोग न करें'

महेश विश्वकर्मा ने कहा कि अगर हमारे उपभोक्ता साथी चाहें तो आवश्यकता के अनुसार बिजली का प्रयोग कर इस ट्रिपिंग की समस्या से भी मुक्ति पा सकते हैं। एक साथ ही घर में लगे बिजली के सारे उपकरणों का प्रयोग ना करते हुए अगर इसे आवश्यकता के अनुसार इस्तेमाल करेंगे तो इससे एक तरफ जहां बिजली की बचत होगी वहीं दूसरी तरफ ट्रांसफॉरमरों पर ज्यादे लोड भी नहीं पड़ेगा। इससे ट्रिपिंग की समस्या में कमी आ जाएगी।

अधिकारियों ने ट्रांसफॉर्मरों का किया निरीक्षण

देर रात हुई बिजली विभाग की गस्त में बिजली विभाग के अधिकारियों ने जनपद मऊ के वितरण खंड द्वितीय के सभी उपकेंद्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में लगे कुछ ट्रांसफॉमेरों का निरीक्षण किया। यहां पर बिजली व्यवस्था पूरी तरह से ठीक पायी गई।

योगी सरकार के फैसले से गाजीपुर के ग्राम प्रधानों में खुशी की लहर, मिठाई बांट जताया आभार

(जीएनएस)।

गाजीपुर। ग्राम प्रधानों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद उन्हें आगामी छह माह तक प्रशासक नियुक्त किए जाने के शासन के निर्णय से क्षेत्र के प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई।

बुधवार को प्रधान संघ के ब्लॉक अध्यक्ष रणजीत सिंह धर्मेंद्र के नेतृत्व में ब्लॉक परिसर में प्रधानों ने एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया तथा प्रदेश सरकार के प्रति आभार जताया।

प्रधानों ने कहा कि कार्यकाल समाप्त होने के कारण कई विकास योजनाएं अधूरी रह गई थीं। अब छह माह तक प्रशासक के रूप में कार्य करने का अवसर मिलने से गांवों में रुके हुए विकास कार्यों को पूरा कराया जा सकेगा।

उन्होंने कहा कि पंचायतों में सड़क, नाली, खड़ंजा, पेयजल, सामुदायिक शौचालय, पंचायत भवन तथा अन्य जनहित की योजनाओं को गति मिलेगी।

ब्लाक अध्यक्ष रणजीत सिंह धर्मेंद्र ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लिया गया यह निर्णय ग्राम पंचायतों के विकास के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।

इससे गांवों में चल रहे विकास कार्य बाधित नहीं होंगे और जनता को योजनाओं का लाभ लगातार मिलता रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधान गांव की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होते हैं और सरकार ने गांवों के विकास को ध्यान में रखते हुए सराहनीय निर्णय लिया है।

प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष रवींद्र यादव ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ग्राम प्रधानों की समस्याओं को समझते हुए सकारात्मक फैसला लिया है। इससे पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था सुचारु बनी रहेगी तथा ग्रामीण विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी।

जयराम यादव, बृजेश यादव, हरेंद्र विश्वकर्मा, बूच्ची यादव, सुरेंद्र यादव, सोनू गुप्ता, राजेश राम, मधु, हीरामणि चौहान, दिलीप कुमार, धनी यादव, जवाहर बिंद तथा राम लक्ष्मण राजभर मौजूद रहे।

PRGI No.: UPHIN/25/A1698 Published & Owned by RAGINI JIGNESHKUMAR VAGHELA and Printed By SUSHILA SHUKLA at Krishna Printiers, 271/31 Chakmaki Dugawa, Rajendranagar, Lucknow-226018, Uttar Pradesh.
and Published from 538 GHA/85 Pataurganj, Near Janki Prasad Dharmshala, Sitapur Road, Niralanagar, Lucknow-226020, Uttar Pradesh. Editor : VINOD KUMARI
Regd.Office : B/13, Sneh Plaza Shopping Center, I.O.C. Road, Chandkheda, Ahmedabad - 382 424 Gujarat,India. Phone : (o) 7698333307 (M) 8485951747,7096333307
Email:navsarjansanskruti2016@gmail.com*navsarjansanskruti2016@yahoo.com*Website : www.navsarjansanskruti.com

सम्पादकीय

क्वाड ने जो सक्रियता दिखाने का संकेत दिया है, उससे वर्तमान की चुनौतियों से निपटने की क्षमता में होगी वृद्धि

क्वाड यानि चतुष्पक्षीय सुरक्षा संवाद के विदेश मंत्रियों की संपन्न हुई मंगलवार की बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने इस संगठन की और अधिक प्रासंगिक, सार्थक और सक्रिय साबित करते हुए हिन्द प्रशान्त क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक स्वर में आह्वान किया।

दरअसल यह बैठक चारों सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की जल्द ही होने वाली शिखर बैठक में भूराजनीतिक दृष्टि से नई दिशा का निर्धारण करने वाले फैसलों की पृष्ठभूमि है। उल्लेखनीय है कि इस वक्त क्वाड की अध्यक्षता भी भारत के पास ही है इसलिए विदेशमंत्री डॉ. एस जयशंकर ने ही इस बैठक की अध्यक्षता की। क्वाड के विदेशमंत्रियों ने दुनिया भर में ईंधन के लिए मचे हाहाहकार के लिए प्रमुख कारण होर्मूज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को रोकने और भारी भरकम टैक्स ठोंकने को भी प्रमुख कारण माना। क्वाड विदेशमंत्रियों ने चीन को भी संदेश देते हुए कहा कि हम क्षेत्र में शांति और स्थिरता को खतरा पहुंचाने वाली, बल प्रयोग या दबाव बनाने वाली हर अस्थिरकारी या एकतरफा कार्रवाई का कड़ा विरोध दोहराते हैं।" असल में क्वाड अपतटीय संसाधनों के विकास हस्तक्षेप, नववाहन या उड़ान भरने की स्वतंत्रता में बार-बार बाधा डालने तथा सैन्य विमानों, तटरक्षक और समुद्री मिलीशिया पोतों की खतरनाक और दबावपूर्ण कार्रवाईयों को लेकर गंभीर चिन्ता व्यक्त करते हैं। क्वाड विदेशमंत्रियों ने विवादित क्षेत्रों के सैन्यीकरण पर भी एतराज किया। सच तो यह है कि क्वाड कोई सैन्य संगठन नहीं है जो किसी देश को निशाने पर लेकर उसे तबाह करने की रणनीति पर विचार करे। सच तो यह है कि क्वाड एक सकारात्मक संगठन है जो किसी भी तरह के विस्तारवाद-दादागिरी का जमकर विरोध करता है। ऐसा नहीं है कि क्वाड कोई ऐसा संगठन है जो किसी, देश को निशाना बनाने के लिए बना है किन्तु यह भी है कि यदि कोई देश दादागिरी करता है तो सदस्य देश आवाज उठाते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि कोई देश अपनी विस्तारवादी मानसिकता से ग्रस्त होकर भूराजनीतिक परिस्थिति को तनावग्रस्त न करे। बहरहाल क्वाड देशों की एकजुटता का लाभ भी दिख रहा है। भारतीय प्रशांत क्षेत्र में अराजकता नहीं दिख रही है। यदि क्वाड प्रयास करे तो संभव है कि होर्मूज जलडमरूमध्य से दुनिया के सभी देशों के जहाजों को रास्ता मिल सकता है। लब्बोलुआब यह है कि क्वाड ने आज जो सक्रियता दिखाने का संकेत दिया है, वह निश्चित रूप से इस संगठन की प्रासंगिकता, वैचारिक एकरूपता और चुनौतियों से निपटने की क्षमता में वृद्धि होगी। साथ ही क्वाड की सदस्यता के लिए जिस तरह से वुछ देश लालायित हैं, उससे भी लगता है कि इस संगठन के माध्यम से क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने और समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सक्रियता एवं

भारत के खिलाफ 'यूक्रेन मॉडल' अपनाने की फिराक में पाकिस्तान, एक्सपर्ट ने दी रूस वाली गलती से बचने की सलाह

(जीएनएस)।

मई 2025 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है जिनमें अब्दाली, फतह-4, तैमूर और फतह-क्क शामिल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और तरीका है जिससे इस्लामाबाद भारत के रणनीतिक फायदे को उसकी रणनीतिक कमजोरी में बदल सकता है।

यूक्रेन के ड्रोन युद्ध के सामने बेबस पाकिस्तान

इस्लामाबादः भारत ने पिछले साल मई महीने में हुए संघर्ष के दौरान अपनी रणनीतिक गहराई का फायदा उठाते हुए आधे घंटे से भी कम वक्त में पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह कर दिए थे। पाकिस्तान का लंबा और संकरा आकार होने की वजह से उसके पास रणनीतिक गहराई नहीं है। पाकिस्तान की पूर्व-पश्चिम में अधिकतम चौड़ाई अपने सबसे चौड़े बिंदु पर सिर्फ 1,125 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि देश का अधिकांश हिस्सा भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों की मारक सीमा के भीतर आता है। खुद पीएम मोदी ने चेतावनी देते हुए कह रखा है कि आतंकवादियों को "छिपने के लिए एक इंच जगह भी नहीं मिलेगी" और उन्होंने यह भी जोड़ा कि "आतंकवादियों के लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं होगी यहां तक कि पाकिस्तान सेना की पनाह में भी नहीं।"

दूसरी तरफ भारत के पास काफी अंदर तक रणनीतिक गहराई और भौगोलिक फायदे हैं। भारत की पूरब से पश्चिम तक की अधिकतम चौड़ाई लगभग 2,933 है जो पाकिस्तान की चौड़ाई से दोगुनी से भी ज्यादा है। पाकिस्तान इस असंतुलन से अच्छी तरह वाकिफ है। अगस्त 2025 में फ्लोरिडा के टैम्पा में एक निजी डिनर कार्यक्रम के दौरान पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगले संघर्ष के दौरान पाकिस्तान भारत को पूरब से पश्चिम तक निशाना बनाएगा। उनकी इन टिप्पणियों का मकसद नई दिल्ली को यह संदेश देना था कि उसे अपने बड़े भूभाग की वजह से सुरक्षा का कोई गलत एहसास नहीं पालना चाहिए।

मई संघर्ष के बाद पाकिस्तान के बड़े मिसाइल टेस्ट

मई 2025 के युद्ध के बाद से पाकिस्तान ने कई लंबी दूरी की मिसाइलों का परीक्षण किया है जिनमें अब्दाली, फतह-4, तैमूर और फतह-क्क शामिल हैं। लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि एक और तरीका है जिससे इस्लामाबाद भारत के रणनीतिक फायदे को उसकी रणनीतिक कमजोरी में बदल सकता है। सच तो यह है कि यूक्रेन पहले से ही दुनिया को यह दिखा रहा है कि किसी देश का आकार उसकी रणनीतिक कमजोरी कैसे बन सकता है।

रूस के अंदर गहराई तक कैसे हमले कर रहा यूक्रेन

पश्चिमी देशों ने जब यूक्रेन को लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें देने से इनकार कर दिया तब यूक्रेन ने नई रणनीति को तेजी से अपनाया। यूक्रेन ने हाल ही में अपनी

नई FP-5 FlÔmi»»fgo क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल शुरू किया है जिसकी मारक क्षमता 3,000 किलोमीटर है हालांकि रूसी इलाके के अंदर गहरे हमले करने के लिए कीव की पहली पसंद लंबी अभी भी दूरी के ड्रोन ही रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच तीन दिन के सीजफायर के बाद दोनों देशों ने एक दूसरे पर रिकॉर्ड संख्या में ड्रोन हमले किए जिससे पता चलता है कि उनके ड्रोन जखीरे लबालब भरे हुए हैं। रूस ने 13 मई से 14 मई के बीच दो दिनों में 1,567 हमलावर ड्रोनों की रिकॉर्ड-तोड़ बौछार की।

इसके जवाब में यूक्रेन ने 16-17 मई की रात को मॉस्को पर एक साल से भी ज्यादा समय का अपना सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया। इस हमले में 600 से ज्यादा ड्रोन इस्तेमाल किए गए और रूस में कम से कम चार लोगों की मौत हो गई। यूक्रेनी ड्रोन हमलों में रूस के येस्क एयरबेस पर एक दुर्लभ बेरीव ई-200 एम्फीबियस विमान और एक डं-27 हेलीकॉप्टर के साथ-साथ एक Tor-M2 सिस्टम और गोला-बारूद रखने की जगहें भी नष्ट हो गईं। इस हमले में मॉस्को पर सैकड़ों ड्रोन हमले भी शामिल थे जिसमें रूसी राजधानी में तीन लोगों की मौत हो गई और बड़ी आग लग गई।

खास बात यह है कि मॉस्को न सिर्फ यूक्रेनी फ्रंटलाइन से 600 किलोमीटर से ज्यादा दूर है बल्कि पूरे रूस में सबसे ज्यादा सुरक्षित जगहों में से एक है जहां सबसे ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। यूक्रेन ने राजधानी में हमला कर अपनी क्षमता साबित कर दी है। रूस के अंदर हजोरों किलोमीटर अंदर और फ्रंटलाइन से काफी दूर किए गए ये सटीक हमले पांच अहम क्षमताओं को दिखाते हैं

1- बेहतरीन इंटेलिजेंस इकट्ठा करना

2- 1,000 किलोमीर से ज्यादा की लंबी दूरी की ड्रोन टेक्नोलॉजी

3- आधुनिक गाइडेंस सिस्टम जिसमें GPS-रहित माहौल में अक-पावर्ड नेविगेशन

4- हाई-बैंडविड्थ सैटेलाइट कनेक्टिविटी

5- फर्स्ट-पर्सन-व्यू (FPV) कंट्रोल शामिल है।

भारतीय वायुसेना के पूर्व पायलट विजयेन्द्र के ठाकुर ने यूरेशियन टाइम्स में लिखा है "धीमी गति से उड़ने वाले यूक्रेनी ड्रोन हवाई सुरक्षा और दृश्य पहचान से बचने के लिए पृथ्वी की सतह के सबसे करीब (NOE) उड़ान भरते हुए और चालाकी से मार्ग बदलते हुए रूसी क्षेत्र में गहराई तक घुसपैठ करते हैं।" उन्होंने कहा "खबरों के मुताबिक वे आवश्यकता पड़ने पर दूरस्थ संचालन के लिए स्टारलिंक लो-लेटेंसी संचार नेटवर्क और नेविगेशन के लिए जीपीएस का उपयोग करते हैं। जब भी जीपीएस या स्टारलिंक सिग्नल काम करना बंद कर देते हैं तो ड्रोन अस्थायी रूप से एआई-आधारित स्वायत्त मशीन-विजन नेविगेशन पर लौट आते हैं। सैकड़ों, कभी-कभी एक हजार से भी ज्यादा किलोमीटर की उड़ान भरने के बाद उन्हें गाइड करते हुए टारगेट पर सटकी हमला करने के लिए पहुंचाया जाता है।"

FPV ड्रोन सबसे ज्यादा खतरनाक कैसे बना?

इजरायली कंपनी XTEND जिसके सिस्टम का इस्तेमाल IDF बड़े पैमाने पर करती है उसने यह साबित कर दिया है कि उसके FPV ड्रोन को दूसरे महाद्वीप से भी उड़ाया जा सकता है भले ही उसमें काफी ज्यादा देरी हो। अमेरिकी ड्रोन MQ-9 ReÔper को दुनिया में लगभग कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है। इसलिए कम देरी वाली सैटेलाइट कनेक्टिविटी के साथ दूरियां और बड़े भूभाग अब बेमानी हो गए हैं। यहां तक कि जिस देश के पास लंबी दूरी की सटीक मिसाइलें नहीं हैं वह भी अपने दुश्मनों पर हजारों मील दूर से हमला कर सकता है। 'नैप-ऑफ-द-अर्थ' (NOE) उड़ान प्रोफाइल का उपयोग करके ड्रोन उन हवाई क्षेत्रों में भी घुसपैठ कर सकते हैं जिनकी हवाई सुरक्षा काफी एडवांस एयर डिफेंस करते हैं।

पाकिस्तान के 'यूक्रेन मॉडल' पर गंभीर नजर रखने की जरूरत

भारत को यूक्रेन मॉडल पर काफी गंभीकता से नजर रखने और अपनी क्षमता बढ़ाने की दिशा में तेजी से काम करना चाहिए। अगले भारत-पाकिस्तान संघर्ष में, पाकिस्तान द्वारा भारत के अंदर गहरे हमले करने के लिए लंबी दूरी के ड्रोन का उपयोग किए जाने की ज्यादा संभावना है। विजयेन्द्र के ठाकुर का मानना है कि पाकिस्तान लंबी दूरी के स्टील्थ ड्रोन का उपयोग कर सकता है और उन्हें ठडए प्रोफाइल में उड़ा सकता है। भारतीय हवाई क्षेत्र में घुसपैठ करने के लिए अपरंपरागत रास्तों का उपयोग कर सकता है और भारत के रिएक्शन पर नजर रखने के लिए चीनी क्रफ संपत्तियों का लाभ उठा सकता है।

मोदी-योगी की जुगलबंदी है कमाल, 2027 में अखिलेश-राहुल-माया सबका होगा बंटाधार!

(जीएनएस)।

लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले विपक्ष, खासकर अखिलेश यादव, यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच दूरी बढ़ गई है. हालांकि जमीन पर दोनों नेताओं की मजबूत जुगलबंदी साफ दिखाई देती है. गंगा एक्सप्रेसवे, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली-मेरठ रैपिड रेल और बुंदेलखंड डिफेंस कॉरिडोर जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स को डबल इंजन सरकार की सफलता के तस्वीर हैं. साथ ही उज्ज्वला, आवास, आयुष्मान और ई-श्रम जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं को यूपी में प्रभावी ढंग से लागू करने का श्रेय योगी सरकार को दिया गया है. लेख के अनुसार विपक्ष बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक नैरेटिव गढ़ने में जुटा है, जबकि मोदी-योगी के बीच मजबूत तालमेल बना हुआ है.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की हवा बनने लगी है. आठ महीने से भी कम समय बचने के चलते बीजेपी, सपा, बसपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल कील कवच दुरुस्त करने में जुट गए हैं. अखिलेश यादव, राहुल गांधी और मायावती की सक्रियता राज्य में बढ़ गई है. इसी बीच विपक्षी नेताओं खासकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के हालिया इंटरव्यू और बयानों पर नजर डालें तो वह एक नैरेटिव गढ़ने के प्रयास में दिखते हैं कि उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच दूरी बढ़ी है. अखिलेश यादव अपने इंटरव्यू में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर तंज भरे लहजे में कहते हैं कि लखनऊ और दिल्ली की दूरी बढ़ गई है.

राजनीति के कुछ जानकार भी इस नैरेटिव को मजबूत करने के प्रयास में दिखते हैं. खासकर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार और बीजेपी की प्रचंड जीत के बाद विपक्ष इस तरह के नैरेटिव को कुछ ज्यादा ही तवज्जो देता दिख रहा है. जबकि धरातल पर नजर डालने पर कहानी बिलकुल उलट नजर आती है. दिखता है कि मोदी और योगी के बीच जबदरस्त जुगलबंदी है. साफ तौर से दिखता है कि इसी जुगलबंदी के चलते उत्तर प्रदेश में डबल इंजन सरकार का असली विकास दिखता है. यूं तो बीजेपी के दोनों बड़े नेताओं के सामंजस्य के अनगिनत उदाहरण हैं, लेकिन आइए उन खास पर नजर डालते हैं जिसके जरिए जुगलबंदी को सरलता से समझा जा सकता है.

पीएम मोदी ने किया गंगा एक्सप्रेस वे का उद्घाटन

गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश सरकार का महत्वाकांक्षी और ड्रीम प्रोजेक्ट है. यह देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स में से एक है. यूपी सरकार की संस्था यूपीडा इस पूरे

प्रोजेक्ट की नोडल एजेंसी है, जिसने जमीन अधिग्रहण से लेकर इसके निर्माण और देखरेख की पूरी जिम्मेदारी संभाली है. यह यूपी के 12 जिलों मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ और प्रयागराज से होकर गुजरता है. इसमें केंद्र सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं है. सीएम योगी चाहते तो इसका उद्घाटन खुद कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया. पीएम नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल, 2026 को हरदोई में इस भव्य गंगा एक्सप्रेसवे के फेज-1 का आधिकारिक उद्घाटन कर इसे जनता के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया.

इसी तरह इसी मार्च के महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ एक साथ नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करते दिखे. इतना ही नहीं पिछले 10 साल में नोएडा और इसके आसपास के इलाकों में उद्योग धंधों की बाढ़ आ गई है. केंद्र सरकार की मदद से कई देशी और विदेशी कंपनियां नोएडा में अपना प्लांट लगा चुकी हैं. इससे पहले पीएम मोदी की मौजूदगी में ही दिल्ली से मेरठ रैपिड रेल की सौगात दी गई. केंद्र सरकार की मदद का ही नतीजा है कि भारत में आज 55% मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अकेले उत्तर प्रदेश में हो रही है. नोएडा में आईटी हब, एआई, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल (एश), फिनटेक और डीप टेक के कई प्रोजेक्ट अपनी रफ्तार से बढ़ रहे हैं.

केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में अव्वल है यूपी

योगी और मोदी की जुगलबंदी का ही कमाल है कि केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं को लागू करने में यूपी अव्वल राज्यों की श्रेणी में है. उज्जवला योजना हो चाहे गरीबों को पक्के मकान देने की बात हर क्षेत्र में सीएम योगी ने केंद्र की योजनाओं को बेहद सफलता पूर्वक धरातल पर उतारा है. उसी तरह 'ई-श्रम' पोर्टल पर पंजीकरण में उत्तर प्रदेश देश में नंबर वन है. निर्माण कामगार मृत्यु सहायता योजना के तहत दुर्घटना में मृत्यु पर 5 लाख और दिव्यांगता पर 4 लाख रुपये तक की सहायता दी जा रही है. इसी तरह श्रमिक की बेटी की शादी के लिए 65,000 से 75,000 रुपये तक की सहायता दी जा रही है. प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना से जरूरतमंदों को निःशुल्क उपचार, अटल आवासीय विद्यालय योजना के तहत वंचित तबके के बच्चों को विश्वस्तरीय और निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है. केंद्र सरकार की ही प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत 7 लाख से अधिक श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा से जोड़ा जा रहा है. अटल पेंशन योजना के तहत यूपी में 93 लाख लाभार्थी हैं.

डबल इंजन सरकार का फल है बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर

उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर अपने आप में केंद्र और राज्य सरकार की एकजुटता का उदाहरण है. यह भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की एक अत्यंत महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और पिछड़े माने जाने वाले बुंदेलखंड क्षेत्र का औद्योगिक कायाकल्प करना है. केंद्र सरकार ने देश में दो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की घोषणा की थी- एक तमिलनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में. उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (UPDIC) के तहत कुल 6 नोड्स (Nodes) बनाए गए हैं, जिनमें से 2 प्रमुख नोड्स विशेष रूप से बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित हैं, पहला झांसी और दूसरा चित्रकूट.

वंदे मातरम पर मोदी-योगी दिखे साथ

राष्ट्रगीत 'वंदे मातरम' के 150 वर्ष पूरे होने पर 8 दिसंबर 2025 को विशेष और विस्तृत चर्चा आयोजित की गई थी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में 'वंदे मातरम' पर जोरदार भाषण दिया. इसके तुरंत बाद उत्तर प्रदेश विधानसभा में शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन 22 दिसंबर 2025 वंदे मातरम के महत्व, इसके इतिहास और राष्ट्रीय चेतना पर बात करने के लिए सदन में करीब 5 घंटे की विशेष बहस कराई गई. विधानसभा में चर्चा के बाद सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश के स्कूलों में वंदे मातरम के संपूर्ण छंद का गायन अनिवार्य कर दिया.

मोदी की मदद से यूपी में नये आर्थिक प्रोग्रेस का रिकॉर्ड बना रहे योगी

पिछले साढ़े नौ साल में उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले राज्यों की लिस्ट में आ गया है. सीएम योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में यूपी 30 लाख करोड़ रुपये से अधिक की जीएसडीपी के साथ तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है. 25 करोड़ की जनसंख्या और 56 फीसदी कार्यशील आयु वर्ग के साथ उत्तर प्रदेश दुनिया के सबसे बड़े श्रम एवं उपभोक्ता बाजारों में से एक बन चुका है. केंद्र सरकार की ओर से मिले बजट और यूपी सरकार की ओर से जुटाए गए संसाधनों के चलते मौजूदा वक्त में 22 एक्सप्रेसवे, 16 घरेलू और 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, 27 इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग और लॉजिस्टिक्स क्लस्टर और पूर्वी व पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन चुके हैं या इसपर तेजी से काम चल रहे हैं.

इसके अलावा अयोध्याजी, वाराणसी जैसे धार्मिक नगरी में जितनी भी विकास कार्य की योजनाएं चल रही हैं उसमें हर जगह केंद्र और राज्य सरकार की एकजुटता नजर आती है. विपक्षी दलों के साथ दिक्कत ही यही है कि वह अपने संगठन पर ध्यान देने के बजाय बीजेपी के खिलाफ झूठा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते रहते हैं. हालांकि पिछले 10-12 साल में विपक्ष का झूठे प्रोपेगेंडा फैलाने में हमेशा से मुंह की खानी पड़ी है. फिर वह अपनी आदतों से बाज नहीं आते हैं. अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर से मोदी-योगी के बीच दूरी का नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन इसमें तनिक भी सच्चाई नजर नहीं आती है.

पीएम मोदी के आह्वान का असरः सोने को छोड़ पीतल नगरी के 'गोल्डन' गहनों पर रीझीं महिलाएं, बिक्री कई गुना बढ़ी

(जीएनएस)।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक वर्ष तक सोना न खरीदने के किए गए आह्वान और आसमान छूती सोने की कीमतों का असर अब साफ दिखने लगा है. बाजारों में सोने की खरीदारी में आई कमी के बीच एक नया ट्रेंड सामने आया है. महिलाएं अब असली सोने की जगह, हूबहू सोने जैसी दिखने वाली पीतल की ज्वेलरी को अपनी पहली पसंद बना रही हैं. पीतल नगरी में बड़े पैमाने पर मिलने वाली यह ज्वेलरी न सिर्फ जेब पर हल्की है, बल्कि लुक में बिल्कुल 'प्योर गोल्ड' को मात देती है. यही वजह है कि इसकी डिमांड और बिक्री में अब कई गुना का बंपर उछाल आ गया है.

प्रधानमंत्री मोदी ने एक वर्ष तक सोना न खरीदने का आह्वान किया था, जिसको लेकर लोगों ने सोने की खरीदारी कम कर दी है. तो वहीं अब सोने की जगह महिलाएं सोने जैसी दिखने वाली धातु यानी पीतल की ज्वेलरी खरीदना ज्यादा पसंद कर रही हैं. यह ज्वेलरी देखने में बिल्कुल सोने

की तरह होती है, जिसकी वजह से महिलाएं अब सोने की जगह इस ज्वेलरी का ज्यादा प्रयोग कर रही हैं. पीतल नगरी में बड़े पैमाने पर पीतल की यह ज्वेलरी मिल रही है.

सोने के बढ़ते दाम और 'पीतल ज्वेलरी' की भारी डिमांड

पीतल की ज्वेलरी के कारोबारी मोहम्मद फैसल ने बताया कि हमारे यहां पीतल की ज्वेलरी में पीतल के बैंगल्स, नेकलेस, चूड़ी, रानी हार, चेन सहित जितनी भी ज्वेलरी होती है, सभी मौजूद रहती है. जब से सोने के रेट बढ़े हैं, तब से महिलाएं इस ज्वेलरी को बहुत पसंद कर रही हैं. इसके अलावा पीएम मोदी ने भी 1 साल तक सोना न खरीदने का आवाहन किया था, जिसके बाद महिलाएं सोने की जगह पीतल की ज्वेलरी को ज्यादा पसंद कर रही हैं और पीतल की ज्वेलरी की जमकर डिमांड आ रही है और बिक्री भी हो रही है.

मात्र 50 रुपये से शुरूआत, दूर-दूर से पहुंच रहे खरीदार

उन्होंने कहा कि इसकी कीमत भी बहुत कम रहती है, 50 रुपये से पीतल की ज्वेलरी की कीमत शुरू होती है. बाकी अलग-अलग साइज और अलग-अलग डिजाइन पर निर्भर करती है, लेकिन यह कीमत 1000 या 2000 रुपये तक ही सीमित रहती है. पीतल की ज्वेलरी बिल्कुल गोल्ड की कॉपी है और देखने में बिल्कुल सोने की तरह दिखती है, जिसकी वजह से महिलाएं इसे ज्यादा खरीद रही हैं. पहले आर्टिफिशियल ज्वेलरी यानी पीतल की ज्वेलरी सेल होती थी, लेकिन पहले के मुकाबले अब कई गुना ज्यादा सेल बढ़ गई है और महिलाएं पहले के मुकाबले ज्यादा खरीद रही हैं. उन्होंने कहा कि इसे खरीदने के लिए उत्तराखंड, रामनगर, काशीपुर सहित दूर-दूर के लोग आते हैं और जमकर खरीदारी करते हैं.

लोगों की जॉब छीन एआई को काम सौंपा, अब खर्चा देख कंपनियों के हाथ-पैर फूल रहे

Uber का साल भर का AI बजट सिर्फ चार महीने में खत्म हो गया. अब उसके सीओओ को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. माइक्रोसॉफ्ट भी अपने कर्मचारियों से एआई का कम इस्तेमाल करने के लिए कह रहा क्योंकि खर्च ज्यादा हो रहा है.

(जीएनएस)।

Uber के COO Andrew Macdonald को समझ ही नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपनी कंपनी में जो पैसा AI पर लगाया, वो सही था या आधा सही. दरअसल कंपनी का 2026 का पूरा एआई बजट सिर्फ चार महीने में खत्म हो गया है. एआई पर कंपनी ने जितना पैसा लगाया, उसके हिसाब से कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है. माइक्रोसॉफ्ट भी कुछ ऐसी समस्या से जूझ रहा है. उसने अपने कर्मचारियों से एआई का कम इस्तेमाल करने को कहा है क्योंकि खर्चा बहुत हो रहा है. माने जिस खर्चे को बचाने के लिए कंपनियों ने कर्मचारी निकाले और उसके बदले एआई को रखा, वो अब हाथी पालने जैसे हो गया है.

क्या एआई का फुग्गा फूट गया है

एकदम नहीं क्योंकि अब फुग्गे में हवा ही पूरे तरीके से नहीं भरी गई तो फूटेगा कैसे. एआई बिला शक कमाल की चीज है मगर टेक कंपनियां उसको बंदर के हाथ में उस्तरे के जैसे इस्तेमाल कर रही हैं. ना सोचा, ना समझा, बस हर जगह एआई घुसेड़ दिया. सिस्टम में एआई लगाना कोई सस्ता सौदा नहीं है. इसके लिए मोटा पैसा खर्च करना पड़ता है.

आप एकदम ठीक पढ़े. आपके पास जो चैटजीपीटी या Claude ऐप है वो बेसिक वर्जन है जो ज्यादातर समय आपकी बे सिर पैर की बातों का जवाब देता है. कंपनी के सिस्टम में फिट करने के लिए इसका पेड वर्जन चाहिए होता है जो बहुत महंगा है. एआई को अपने सिस्टम में फिट करने में ऊबर सबसे आगे है. उसके पूरे सिस्टम में अब काम एआई एजेंट के जरिए हो रहा है मगर इसकी लागत अब उसके हाथ से निकल रही है.

महिला ने निजी इस्तेमाल के लिए मंगाया सामान, देखते ही डिलीवरी बॉय ने किया भद्दा कमेंट, बोला- 'मेरे रहते इसकी...'

(जीएनएस)।

ब्लिंकिट से प्राइवेट प्रोडक्ट मंगाने वाली एक महिला ने डिलीवरी एजेंट पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है. महिला की पोस्ट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर बहस तेज हो गई है.

आज के दौर में ऑनलाइन डिलीवरी ऐप्स लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुके हैं. खाने-पीने की चीजों से लेकर दवाइयों और पर्सनल प्रोडक्ट्स तक, लोग घर बैठे सबकुछ ऑर्डर कर लेते हैं. खासतौर पर क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स ने लोगों

की जिंदगी काफी आसान बना दी है. लेकिन हाल ही में एक महिला के साथ डिलीवरी के दौरान जो घटना हुई, उसने महिलाओं की सुरक्षा और प्राइवेसी को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एक महिला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लिंक्डइन पर अपना दर्द शेयर करते हुए बताया कि ब्लिंकिट के एक डिलीवरी पार्टनर ने उसके साथ बेहद आपत्तिजनक व्यवहार किया. महिला का कहना है कि यह अनुभव उसके लिए काफी डरावना और परेशान करने वाला था, क्योंकि डिलीवरी एजेंट उसके घर का पता भी जानता था.

लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएच.डी. कोर्सों में प्रवेश के आवेदन शुरू, 30 जून तक रहेगा मौका

(जीएनएस)।

लखनऊ। लखनऊ विश्वविद्यालय ने सत्र 2026-27 के अंतर्गत पीएच.डी पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए बुधवार से आनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू करते हुए इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस बार पीएच.डी रेगुलर के 41 विषयों की 1060 सीटों और पार्ट टाइम के 30 विषयों की 374 सीटों पर प्रवेश का मौका मिलेगा।

समन्वयक प्रवेश प्रो. अनित्य गौरव ने बताया कि अभ्यर्थी लवि की वेबसाइट पर दिए गए समर्थ पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसकी अंतिम तिथि 30 जून है। जारी विवरण के अनुसार रेगुलर में लवि की 578 और कालेजों की 482 सीटें हैं।

तीन चरणों में होंगे प्रवेश

इइस बार प्रवेश तीन चरणों में होंगे। पहले चरण में यूजीसी-जेआरएफ, सीएसआइआर-जेआरएफ, आइसीएमआर, डीबीटी-जेआरएफ और आइसीटीई जैसी राष्ट्रीय फैलोशिप परीक्षाएं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा।

दूसरे चरण में बची सीटों पर यूजीसी-नेट या सीएसआइआर-नेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को साक्षात्कार होगा। इसमें वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी प्रवेश के लिए नेट परीक्षा क्वालिफाई की हो। तीसरे चरण में यदि सीटें शेष रहती हैं तो विश्वविद्यालय स्तर पर आयोजित रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कोर्स वार सीटें

एआइएच 19, एंथ्रोपोलाजी 14, अप्लाइड इकोनामिक्स 34, अरब कल्चर 15, अरेबिक चार, बायोकेमिस्ट्री सात, बाटनी 35, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आठ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दो, इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियरिंग आठ, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग 30, अप्लाइड साइंस एंड 'मैनिटीज 12, केमिस्ट्री 68, कामर्स 67, इकोनामिक्स 56, एजुकेशन 50, इंग्लिश 30, फ्रेंच आठ, जाग्रफी 15, जियोलाजी छह, हिंदी 47, फार्मास्यूटिकल साइंसेज 26, इंस्टीट्यूट आफ टूरिज्म स्टडीज चार, ला 40, लाइब्रेरी एंड इंफार्मेशन साइंस तीन, मैनेजमेंट स्टडीज 80, मैथमेटिक्स 21, मेडिविअल एंड माडर्न हिस्ट्री 18, ओरियंटल संस्कृत एक, फिलासफी 10, फिजिकल एजुकेशन 21, फिजिक्स 67, पालीटिकल साइंस 60, साइकोलाजी 13, संस्कृत 28, सोशल वर्क 20, सोशियोलाजी 52, स्टैटिस्टिक्स सात, वेस्टर्न हिस्ट्री तीन, जूलाजी 49 सीटें।

'अगर बकरे की कुबार्नी दी तो हम...', लखनऊ के कसमंडी किला बनाम मजार विवाद के बीच पासी समाज की चेतावनी

योगेश पासी ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर बकरीद पर कसमंडी किले में बकरों की कुबार्नी दी गई तो विरोध स्वरूप सूअर की बलि देने का काम किया जाएगा.

(जीएनएस)।

लखनऊ के कसमंडी क्षेत्र को लेकर एक बार फिर विवाद गहराता नजर आ रहा है. पासी समाज से जुड़े योगेश पासी का दावा है कि कसमंडी की जमीन महाराजा कंस पासी की विरासत है और इसी वजह से इस इलाके का नाम कसमंडी पड़ा था. योगेश पासी का कहना है कि पिछले चार वर्षों से लगातार इस मुद्दे को उठाया जा रहा है. उनका आरोप है कि संबंधित स्थान पर अनैतिक तरीके से नमाज अदा की जा रही है. इस संबंध में कई बार प्रशासन को ज्ञापन भी सौंपा गया, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई.

योगेश पासी का यह भी कहना है कि अब युवा समाज जाग चुका है और बड़ी संख्या में लोग उनके समर्थन में आगे आ रहे हैं. उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि बकरीद नजदीक है और अगर त्योहार के दिन वहां बकरों की कुबार्नी दी गई तो विरोध स्वरूप सूअर की बलि देने का काम किया जाएगा.

'जमीन हथियाई तो कोर्ट जाएगा पासी समाज'- योगेश पासी

इसके साथ ही योगेश पासी ने आरोप लगाया कि जमीन को हथियाने की कोशिश की गई है. पासी समाज अब इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएगा और कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी. मामले को लेकर इलाके में चर्चा तेज हो गई है. हालांकि प्रशासन की ओर से अभी तक इस बयान पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

हिंदूवादी संगठनों ने की पूजा

मलिहाबाद के कसमंडी कलां में विवादित स्थल पर हिन्दू संगठन पूजा पाठ करने पहुंचा, तब विवाद बढ़ गया. हिंदूवादी संगठनों ने यहां सांकेतिक पूजा की और इसी के साथ पाठ भी पढ़ा. प्रशासन ने इस स्थल पर बकरीद की नमाज पर रोक लगा दी है. ऐसे में अब हिन्दू संगठनों का कहना है कि यहां अगर शुक्रवार को नमाज हुई तो अब पूजा करेंगे. साथ ही प्रशासन को ज्ञापन दिया और इस मामले को कोर्ट में ले जाने की बात कही.

हिन्दू संगठन को पुलिस ने रोका

विवादित स्थल पर पहुंचने पर हिंदू महासभा को रोक दिया गया. इसलिए हिंदू महासभा के लोगों ने परिसर से लगभग 200 मीटर की दूरी सांकेतिक पूजा की. हिंदू महासभा के प्रवक्ता शिशिर चतुवेर्दी ने कहा कि उन्होंने यहां कानून का पालन किया है. 200 मीटर दूरी से सांकेतिक पूजा की गई है. यह लड़ाई कानूनी रूप से लड़ी जाएगी.

शिशिर चतुवेर्दी ने आगे कहा कि मौलाना की गिरफ्तारी होनी चाहिए और पासी समाज के लोगों को यह मंदिर सौंप दिया जाना चाहिए. फिलहाल, मौके पर पूरी तरीके से शांति है पुलिस और पीएसी जवानों की तैनाती की गई है.

सुंदर कांड का पाठ करने पहुंचे कई लोग

कंसा पासी के कथित किले का विवाद बढ़ते देख पुलिस ने उस ओर जाने वाले रास्ते पर बैरिकेड लगा दिए हैं. चप्पे-चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है. एक के बाद जब दूसरा संगठन वहां पहुंचा, तब पुलिस ने उनको समझा बुझाकर शांत कराया और ज्ञापन लिया. मांग यह थी कि किले के भीतर मजार कैसे बनी? मौलाना को चिन्हित कर कार्रवाई हो.

पासी समाज में आक्रोश

प्रशासन ने बकरीद पर यहां नमाज अदा नहीं करने का आदेश दिया है लेकिन आगे की स्थिति को लेकर पासी समाज में आक्रोश व्याप्त है. इस स्थल को लेकर अभी विवाद और भी गहरा होने की उम्मीद है.

सहारनपुर से 4 आतंकवादी गिरफ्तार, लखनऊ-नोएडा सहित कई शहरों में अस्पताल-स्कूलों को बम से उड़ाने की थी साजिश

(जीएनएस)।

लखनऊ। आतंकवाद निरोधक दस्ता (एटीएस) और स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को सहारनपुर से चार आतंकियों को गिरफ्तार किया है। चारों आतंकी पाकिस्तानी गैंगेस्टर शहजाद भट्टी व आबिद जट के लिए स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। इन्हें लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद सहित अन्य शहरों में स्कूलों व अस्पतालों को बम से उड़ाने का लक्ष्य दिया गया था। इसके लिए आतंकियों ने कई स्कूलों व अस्पतालों की रेकी भी की थी। साथ ही असलहों व विस्फोटक सामग्री उपलब्ध कराने के लिए नोएडा में बैठक भी की थी।

एडीजी कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश ने बताया कि पाकिस्तानी गैंगेस्टर शहजाद भट्टी ने इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म इंस्टाग्राम व यू-ट्यूब के जरिए चारों आतंकियों को अपने साथ जोड़ा था। इन्हें एक राजनीतिक दल के कार्यालय को भी बम से उड़ाने का लक्ष्य दिया गया था। एटीएस थाने में इनके विरुद्ध देश विरोधी साजिश रचने के मामले में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है।

एटीएस के सूत्रों के अनुसार गिरफ्तार आतंकी गगनदीप सिंह उर्फ गुरी सिंह ने बताया कि उसकी और महकाब की कुछ दिन पहले नोएडा में मुलाकात हुई थी। इस मुलाकात में स्कूलों व अस्पतालों को बम से उड़ाने के लिए विस्फोटक सामग्री व असलहे खरीदने के लिए फंड के इंतजाम पर बात हुई थी।

पाक गैंगेस्टर ने इन्हें पहले एक घटना को अंजाम देने का लक्ष्य दिया था और कहा था कि घटना को अंजाम देने के बाद उन्हें फंड उपलब्ध करा दिया जाएगा। आतंकियों ने यह भी बताया कि पाकिस्तानी गैंगेस्टर ने उन्हें कई स्कूलों को संचालित करने वाले एक व्यक्ति को बम से उड़ाने का लक्ष्य दिया था, लेकिन अभी तक आतंकियों ने संबंधित व्यक्ति का नाम नहीं बताया है।

इन्हें किया गया है गिरफ्तार

-22 वर्षीय महकाब पुत्र हसरत, निवासी ढीक्का कला सहारनपुर

-20 वर्षीय शाहरुख, पुत्र इकराम, निवासी ढीक्का कला, सहारनपुर

-25 वर्षीय गगनदीप सिंह उर्फ गुरी सिंह, पुत्र हरजीत सिंह, निवासी शाहपुर, मुजफ्फरनगर

-22 वर्षीय मुशर्रफ, पुत्र मुबारिक, निवासी ढनढेरा, हरिद्वार।

'नियम बदले तो सबके लिए बदलें...' योगी के फरमान पर सहारनपुर के मुस्लिम समाज ने उठाए सवाल, कही यह बात

बकरा ईद से पहले सड़कों पर नमाज न पढ़ने के सीएम योगी आदित्यनाथ के कड़े आदेश पर सहारनपुर के मुस्लिम समाज की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. स्थानीय लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताते हुए मांग की है कि नियम कांवड़ यात्रा और जागरण जैसे सभी धार्मिक आयोजनों पर समान रूप से लागू हों. वहीं, कुछ युवाओं ने देश में मीट को पूरी तरह बैन करने की अनोखी मांग उठाकर सबको चौंका दिया है.

(जीएनएस)।

सहारनपुरः बकरा ईद (ईद-उल-अजहा) से ठीक पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 'सड़कों पर नमाज न पढ़ने' वाले कड़े बयान ने सियासी और सामाजिक हलचल तेज कर दी है. सीएम योगी के इस फरमान और 'दूसरा तरीका अपनाने' की चेतावनी पर अब देश के सबसे बड़े मुस्लिम शिक्षण संस्थान के गढ़, सहारनपुर के मुस्लिम समाज की बड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है. स्थानीय लोगों ने इसे राजनीतिक स्टंट बताने से लेकर, सभी धर्मों के लिए समान नियम लागू करने और यहाँ तक कि देश में मीट को पूरी तरह बैन करने जैसी हैरान करने वाली राय रखी है. आइए जानते हैं कि इस आदेश को लेकर सहारनपुर का मुस्लिम समाज क्या सोचता है.

मुख्यमंत्री के आदेश सभी धर्मों के लिए होने चाहिए बराबरः डंपी

मुस्लिम समाज के स्थानीय निवासी डंपी ने बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री जी प्रदेश के मुखिया हैं, वह कोई भी आदेश जारी कर सकते हैं. लेकिन हमारा मानना यह है कि जैसा आदेश मुस्लिम समाज के लिए जारी हो रहा है, वैसा ही नियम सभी के लिए होना चाहिए. हिंदुओं के त्योहार भी सड़कों पर होते हैं जैसेः कांवड़ यात्रा, जागरण और शोभायात्राएं. अगर पाबंदी लगानी है तो सब पर बराबर लगे, किसी एक पक्ष पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.

रही बात ईद पर नमाज की, तो यह साल में सिर्फ एक बार होती है. सहारनपुर हमेशा से हिंदू-मुस्लिम एकता की मिसाल रहा है. एक दौर था जब जुमे की नमाज के वक्त मस्जिद फुल होने पर लोग सड़क पर नमाज पढ़ लेते थे, और अगर किसी मुस्लिम भाई के पास बिछाने के लिए कपड़ा नहीं होता था, तो हिंदू भाई उसे अपना कपड़ा दे देते थे. आज वह मिसाल कहां चली गई? हम कल भी भाई-भाई थे और आज भी हैं. सड़कों पर त्योहार मनाने पर पाबंदी सब पर समान रूप से लागू हो, क्योंकि नमाज के वक्त सड़क पर नमाजियों से ज्यादा तो खुद प्रशासन मौजूद रहता है.

मुस्लिम समाज के अब्दुल खालिक ने कहा कि ऐसे आदेश पहले भी आ चुके हैं और लोग इनका पालन करते हुए सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ रहे हैं. वह हमारे मुख्यमंत्री हैं और उनके आदेशों का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है. सीएम योगी हमें अपना मानें या न मानें, लेकिन हम उन्हें अपना मानते हैं. इस तरह के बयान सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट हैं. रही बात कुबार्नी (कटान) की, तो लोग सड़कों पर नहीं बल्कि अपने घरों या चिन्हित स्थानों पर करते हैं. अगर सरकार को कोई दिक्कत है, तो वह हमारे लिए जगह चिन्हित कर वहां पूरी व्यवस्था कर दे, सब लोग वहीं जाएंगे.

दूसरे देशों में भी यही नियम है. वैसे मेरा तो यह मानना है कि जिस तरह मोदी और योगी जी 'हिंदू सम्राट' हैं, उन्हें भारत में मीट को पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए और विदेशों में इसकी सप्लाई बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए, भले ही सरकार को इससे कितना भी मोटा राजस्व (रेवेन्यू) क्यों न मिलता हो.

ईद आते ही शुरू हो जाती है इनकी राजनीतिः तंजीम नवाज

तंजीम नवाज का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान विशुद्ध रूप से एक राजनीतिक स्टंट है. पिछली बार भी ऐसा ही आदेश आया था और हम सबने इसका पालन करते हुए मस्जिदों और ईदगाहों के अंदर नमाज अदा की थी. योगी जी भी यह सच जानते हैं, लेकिन अगर वह ऐसा बयान नहीं देंगे तो राजनीति कैसे चमकेगी? ईद आते ही इनकी राजनीति शुरू हो जाती है क्योंकि इनका वजूद इसी पर टिका है.

रही बात मीट बैन करने की, तो भारत आज मीट एक्सपोर्ट में नंबर वन पर पहुंच चुका है, सरकार इसे कैसे बंद करेगी? वैसे भी मीट बंद होने से मुस्लिमों को कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मुस्लिम समाज से ज्यादा हिंदू समाज के लोग मीट खाते हैं.

लखनऊ छात्रा गैंगरेप कांडः 18 सिम कार्ड बदलकर पुलिस को छका रहे आरोपी शिवम और शनि, दोनों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप के फरार आरोपियों, शिवम और शनि यादव, पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित हुआ है. वे 18 सिम कार्ड बदलकर ठिकाने बदल रहे हैं. पीड़िता को बंधक बनाकर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया था। पुलिस की चार टीमें जांच में जुटी हैं.

(जीएनएस)।

लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी इलाके में यूपीएससी की तैयारी कर रही छात्रा से गैंगरेप का मामला सुर्खियों में है. मुख्य आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त बाहर हैं. ऐसे में पुलिस ने जौनपुर निवासी छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी शिवम यादव और उसके साथी शनि यादव पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दोनों आरोपियों ने फरारी के दौरान करीब 18 सिम कार्ड बदले और लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, जिससे उनकी लोकेशन ट्रेस करने में दिक्कत आ रही है.

पीड़िता ने मंगलवार को न्यायालय में अपने बयान दर्ज कराए. वहीं पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध युवक को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है और आरोपियों के संपर्कों की जांच की जा रही है.

जांच के दौरान यह भी पता चला कि पीड़िता पहले भी दो बार शिवम के साथ लखनऊ में रुकी थी. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है.

पुलिस की एक टीम सोमवार को प्रयागराज पहुंची और शिवम यादव के संभावित ठिकानों पर दबिश दी, हालांकि उसके परिवार ने पुलिस को बताया कि वह घर नहीं आया है.

पीड़िता दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेज में बीए ऑनर्स की छात्रा है और यूपीएससी की तैयारी कर रही है. आरोप है कि 15 मई को दिल्ली जाते समय उसने परिचित शिवम यादव को मैसेज किया था, जिसके बाद आरोपी उसे चारबाग स्टेशन से सुशांत गोल्फ सिटी स्थित कमरे पर ले गए.

पीड़िता का आरोप है कि वहां उसे नशीला पदार्थ देकर तीन दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया और सामूहिक दुष्कर्म किया गया. तबीयत बिगड़ने पर 18 मई को आरोपियों ने उसे ट्रेन से दिल्ली भेज दिया और फरार हो गए.

दिल्ली के आनंद विहार जीआरपी में दर्ज जीरो एफआईआर को लखनऊ ट्रांसफर किए जाने के बाद सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है. मामले की जांच के लिए चार पुलिस टीमें गठित की गई हैं.

लखनऊ के निगोहां में टूटकर घर पर गिरा हाईटेंशन लाइन का तार, बड़ा टला हादसा

अचानक हुए धमाकों से मोहल्ले में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन काफी देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया। .. तार गिरते ही धमाके के साथ होने लगा शार्ट सर्किट, ग्रामीणों ने देर रात तक किया हंगामा, पुलिस ने उत्तेजित ग्रामीणों को कराया शांत

लखनऊ। राजधानी के निगोहां में मंगलवार देर रात्रि को स्टेशन मार्ग पर हाईटेंशन लाइन का तार टूट गया। टूटा तार वहां पक कारपेंटर के घर में जा गिरा और उसके जमीन पर तार गिरते ही जोरदार धमाके के साथ शॉर्ट सर्किट होने लगा।

इस घटना के बाद निगोहां कस्बा, निगोहां गांव, बैरीसालपुर, शेरपुर लवल, पटिसा, रत्नापुर, भगवानपुर, गोसाईखेड़ा सहित दो दर्जन से अधिक गांवों की बिजली कई घंटे ठप रही।

शॉर्ट सर्किट होने के समय घर के लोग बाहर बैठे थे, इसी वजह से पूरा परिवार बाल-बाल बच गया। जमीन पर तार के गिरते ही तेज विस्फोट होने लगा और कई जगह की पक्की फर्श भी उखड़ गई। अचानक हुए धमाकों से मोहल्ले में भगदड़ मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत बिजली विभाग को फोन किया, लेकिन काफी देर तक किसी ने फोन नहीं उठाया।

विभाग की लापरवाही से ग्रामीणों में आक्रोश फैल गया। घटना के काफी देर बाद सप्लाई बंद की गई। सूचना पर पहुंची विद्युत विभाग की टीम को देखते ही स्थानीय लोग भड़क गए। ग्रामीणों ने तार जोड़ने से मना कर दिया और घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन को तुरंत हटाकर दूसरे रास्ते से शिफ्ट करने की मांग को लेकर हंगामा शुरू कर दिया।

मौके पर पहुंची निगोहां पुलिस ने ग्रामीणों को समझाया। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि लाइन जल्द दूसरे रास्ते से शिफ्ट की जाएगी। इसके बाद समेसी पावर हाउस से नया तार मंगवाकर जोड़ा गया। रात करीब दो बजे विद्युत आपूर्ति बहाल हो सकी।

इस घटना के बाद निगोहां कस्बा, निगोहां गांव, बैरीसालपुर, शेरपुर लवल, पटिसा, रत्नापुर, भगवानपुर, गोसाईखेड़ा सहित दो दर्जन से अधिक गांवों की बिजली कई घंटे ठप रही। जिससे भीषण गर्मी में उपभोक्ताओं को रातभर जागना पड़ा।

ग्राम प्रधान अभय दीक्षित ने बताया कि हाईटेंशन लाइन दर्जनों घरों की छतों को छूते हुए गुजर रही है। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। विभाग के अधिकारियों से मिलकर लाइन को बगल के रास्ते से शिफ्ट करने की बात कही है।

यूपी की डिजिटल क्रांति की ओर तेज रफ्तार, योगी सरकार का 'प्रोजेक्ट गंगा' होने जा रहा लाइव; गांवों में दौड़ेगा हाई-स्पीड इंटरनेट

(जीएनएस)।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजनरी नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अब डिजिटल आत्मनिर्भरता की एक नई इबारत लिखने जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों को आधुनिक तकनीकी मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार का बेहद महत्वाकांक्षी 'प्रोजेक्ट गंगा' अब जल्द ही धरातल पर "लाइव" होने के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार ने इस दूरगामी परियोजना से जुड़े लगभग सभी तकनीकी और प्रशासनिक माइलस्टोन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, जिससे गांवों और छोटे शहरों में डिजिटल क्रांति का रास्ता साफ हो गया है।

माइलस्टोन पूरे, जुलाई 2025 से चल रही थी तैयारी

इस ऐतिहासिक मिशन की रूपरेखा जुलाई 2025 में प्रारंभिक सीडिंग के साथ शुरू हुई थी, जिसने दिसंबर 2025 में विभिन्न सरकारी विभागों की रणनीतिक चचाओं के साथ गति पकड़ी। जनवरी 2026 में इसके कॉन्सेप्ट नोट के बाद, 9 मार्च 2026 को वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना की गरिमामयी उपस्थिति में इसका एमओयू (टङ्कव) साइन किया गया। फाइनल डीपीआर (उढफ) तैयार होने और अप्रैल 2026 में बैंकिंग पार्टनर्स के साथ फाइनेंशियल एनेबलमेंट की बातचीत पूरी होने के बाद, अब यह प्रोजेक्ट जमीनी स्तर पर लागू होने के अंतिम पड़ाव पर है।

गांवों तक पहुंचेगा वर्ल्ड-क्लास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर

प्रोजेक्ट गंगा का मुख्य उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच के डिजिटल डिवाइड (तकनीकी अंतर) को हमेशा के लिए समाप्त करना है।

संकट के इस समय में विदेश यात्राओं पर क्यों जा रहे हैं प्रधानमंत्री, क्या मिल रहा है

(जीएनएस)।

नई दिल्ली, आज दुनिया अभूतपूर्व आर्थिक अस्थिरता, ऊर्जा संकट, भू-राजनीतिक तनाव और आपूर्ति श्रृंखला की चुनौतियों का सामना कर रही है. रूस-यूक्रेन युद्ध, पश्चिम एशिया में अस्थिरता, तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव, वैश्विक मंदी की आशंका और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा ने विश्व अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया है. ऐसे समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार विदेश दौरे केवल कूटनीतिक औपचारिकता नहीं, बल्कि भारत की आर्थिक सुरक्षा, ऊर्जा जरूरतों, रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक नेतृत्व को मजबूत करने की रणनीति के रूप में सामने आए हैं.

प्रधानमंत्री की विदेश नीति का मूल उद्देश्य 'भारत प्रथम' की अवधारणा के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत के हितों को सुरक्षित करना, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, तकनीकी सहयोग बढ़ाना और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था में भारत की भूमिका को सशक्त बनाना है. पीएम मोदी ने पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात, नार्वे, इटली, स्वीडज और डेनमार्क की यात्रा की. आइए देखते हैं कि इस यात्रा से भारत को क्या हासिल होगा.

विश्व राजनीति में आज आर्थिक कूटनीति का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है. किसी भी देश की शक्ति केवल सैन्य क्षमता से नहीं, बल्कि उसके आर्थिक संबंधों, ऊर्जा संसाधनों और वैश्विक साझेदारियों से भी तय होती है. भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता देश है.

भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का करीब 85 फीसद तेल आयात करता है. ऐसे में तेल संकट भारत की अर्थव्यवस्था पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालता है. रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद वैश्विक तेल बाजार में भारी अस्थिरता उत्पन्न हुई. कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि से भारत में महंगाई, व्यापार घाटा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ा.

इसके अतिरिक्त वैश्विक मंदी की आशंका ने निर्यात आधारित अर्थव्यवस्थाओं को भी प्रभावित किया. ऐसी परिस्थिति में प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं कई कारणों से आवश्यक हो गईं, इनमें ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना, वैकल्पिक तेल और गैस आपूर्ति स्रोत विकसित करना, विदेशी निवेश आकर्षित करना, नई तकनीकों और हरित ऊर्जा सहयोग को बढ़ाना, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भूमिका मजबूत करना, भारत को विनिर्माण और निवेश केंद्र के रूप में स्थापित करना आदि शामिल है. प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी विदेश नीति में 'बहु-संरेखीय कूटनीति' को अपनाया है. इसमें भारत अमेरिका, रूस, यूरोप, खाड़ी देशों और एशियाई देशों सभी के साथ संतुलित संबंध बनाए हुए है.

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)आज भारत का एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा साझेदार बन चुका है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विभिन्न विदेश यात्राओं के दौरान भारत और वअए के बीच कई ऐतिहासिक समझौते हुए. जिन्होंने दोनों देशों के संबंधों को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया. दोनों देशों के बीच लागू किया गया व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (कम्प्रेहैंसिव इकनोमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट) द्विपक्षीय व्यापार को तेजी से बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.इसके माध्यम से व्यापारिक बाधाओं को कम कर निवेश और निर्यात को प्रोत्साहन मिला है. इसके अतिरिक्त भारतीय रुपया और यूएई दिरहम में व्यापार करने की सहमति से डॉलर पर निर्भरता कम होने और विदेशी मुद्रा की बचत में सहायता मिली है. ऊर्जा क्षेत्र में तेल भंडारण, एलएनजी आपूर्ति और नवीकरणीय ऊर्जा सहयोग से भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती प्राप्त हुई है.वहीं फिनटेक और डिजिटल भुगतान प्रणाली के अंतर्गत भारत के यूपीआई और यूएई की डिजिटल व्यवस्था के बीच सहयोग ने आधुनिक डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया है. इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह, लॉजिस्टिक्स, स्मार्ट सिटी और औद्योगिक परियोजनाओं में यूएई के निवेश ने भारत में रोजगार और आर्थिक विकास के नए अवसर पैदा किए हैं. इन समझौतों का एक महत्वपूर्ण लाभ यह भी है कि खाड़ी क्षेत्र में भारत की रणनीतिक स्थिति अधिक मजबूत हुई है. वहां रहने वाले भारतीय प्रवासी समुदाय के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित हुई है. अब भारत एक बड़े निवेश गंतव्य, तकनीकी साझेदार और वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरकर सामने आया है.

इटली के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया कूटनीतिक सक्रियता ने भारत-इटली संबंधों को एक नया रणनीतिक आयाम प्रदान किया है. लंबे समय तक दोनों देशों के संबंध मुख्यतः व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान तक सीमित रहे, लेकिन वर्तमान वैश्विक आर्थिक और भू-राजनीतिक परिस्थितियों में दोनों देशों ने अपने संबंधों को 'रणनीतिक साझेदारी' के स्तर तक उन्नत कर यह स्पष्ट संकेत दिया है।